

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग सात

वर्ष ५, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, जून १३-१९, २०१९/ज्येष्ठ २३-२९, शके १९४१ [पृष्ठे ४३ किंमत : रुपये ३७.००

## प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

## अनुक्रमणिका

		पृष्ठे	
<b>महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन २०१७.</b> — मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		२	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन २०१७.— महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति तथा (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		8	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन २०१७.— महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७।	• •	६	
<b>महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन २०१७.</b> — महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		۷	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन २०१७.— महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७।		१२	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन २०१७.— महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		१९	
<b>महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन २०१७.</b> — महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		२१	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन २०१७.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७।		२२	
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन २०१७.— डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्वशांति विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७।		२४	
<b>महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन २०१७.</b> — महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, २०१७।		४२	

#### MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2017.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १३ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्र. हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2017.

# AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MINICIPAL CORPORATION ACT.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दिशत प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सन् १८८८ सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसिलये, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, ३ का ३। सन् २०१७ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत अध्या. क्र. गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

- १. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।
- (२) यह ३ जनवरी, २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- सन् १८८८ का ३ **२.** मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ९२ के, खण्ड (घ घ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया सन् १८८८ की धारा ९२ में जायेगा, अर्थात् :— संशोधन।

"(घ घ-१) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, निगम की मंजूरी से और राज्य सरकार के अनुमोदन से, स्वर्गीय श्री. बालासाहब ठाकरे के स्मारक का निर्माण करने के प्रयोजन के लिये संस्था रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रिजस्ट्रीकृत बालासाहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक नामक सन् १८६० संस्था को, निगम से संबंधित स्थावर संपत्ति, अर्थात् सीटीएस/एफपी क्र. ५०१, ५०२ तथा १४९५ माहिम का २१। विभाग, उस पर स्थित संरचना के साथ, के पट्टे की मंजूरी, जिसमें, ऐसे पट्टे की मंजूरी के लिये एक रुपये के नाममात्र भाटक पर हो और राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विनिश्चित किया जाए ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन दे सकें ;"।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र.

१।

(१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१७ एतदुद्वारा, निरसित किया जाता हैं।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. १ का निरसन तथा व्यावृत्ती ।

सन् १८८८

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम के अधीन का ३। कृत या की गई कोई बात (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई, समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS AND MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्रकाश हिं. माली. प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा सन् १९५९ पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; का ३। और, **इसलिये,** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, ३१ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित किया था ;

का महा. सन् २०१७ का महा.

अध्या. क्र.

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड्सठवें वर्ष में, एतदुद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :--

- (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिती तथा संक्षिप्त नाम तथा <sup>प्रारंभण ।</sup> (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए ।
  - (२) यह ३१ जनवरी, २०१० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- २. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा १४ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ञ-५) में, **''ग्राम सभा** सन् १९५९ की धारा १४ में के" शब्दों के पश्चात्, "या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी के ; या के का ३। संशोधन। स्व-प्रमाणपत्र से" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा १६ की, उप-धारा (१) के, सन् १९६२ का सन् १९६२ का <sup>महा.</sup> खण्ड (त) में **''ग्राम सभा के''** शब्दों के पश्चात्, ''या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा पदाभिहित किसी <sup>महा.</sup> ५ की धारा <sup>५।</sup> अधिकारी के ; या के स्व-प्रमाणपत्र सें" शब्द निविष्ट किए जायेंगे। १६ में संशोधन।

४. (१) महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, सन् २०१७ सन् २०१७ का का <sup>महा.</sup> २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। अध्या. क्र.

महा. अध्या. क्र. ५ का निरसन

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत और महाराष्ट्र तथा व्यावृती। सन् १९५९ जिला परिषद तथा पंचायत सिमिति अधिनियम, १९६१ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई का २। सन् १९६२ कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के का महा. ५। तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2017.

THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १३ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2017.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES ACT, 2005.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

### महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था :

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके सन् २००६ कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और **इसलिये,** महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, ९ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् २०१७ का महा.

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत अध्या. क्र. गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतदुद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— 81

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

- (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।
- (२) यह ९ जनवरी २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- महाराष्ट्र राज्य पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा सन् २००६ सन २००६ का महा. ३४ की धारा १ की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) में, "छह सदस्य, प्रत्येक में से एक सदस्य" शब्दों के स्थान का महा. ३ में संशोधन। 186 में, "आठ सदस्य, प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य" शब्द रखे जायेंगे।

(१) महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतदुद्वारा, निरसित किया सन् २०१७ सन २०१७ का महा. अध्या. क्र. जाता है। का महा. ४ का निरसन अध्या. क्र. तथा व्यावृत्ती।

४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2017.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १३ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,

प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के सन् १९६६ लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, **इसलिए,** महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, ५ जनवरी २०१७ को प्रख्यापित किया गया था;

का महा. सन् २०१७ का महा.

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के अड्सठवे वर्ष में, एतदुद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :--

अध्या. क्र.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

- १. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।
- (२) यह ५ जनवरी २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
- महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता १९६६ (जिसे इसमें आगे, " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा ४२ क सन् १९६६ महा. ४१ की धारा के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— का महा. ४१।

सन् १९६६ का ४२ख और ४२ग की निविष्टि।

> **" ४२ख.** (१) धाराएँ ४२, ४२क, ४४ तथा ४४क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, महाराष्ट्र सन् १९६६ प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अनुसार, किन्ही क्षेत्र में अंतिम विकास योजना के प्रकाशन पर, यदि उप-धारा (२) में यथा उपबंधित संपरिवर्तन कर, अकृषक निर्धारण तथा जहाँ लागू हो, **नजराना** या प्रीमिअम तथा अन्य सरकारी देयों का भुगतान किये गये है, ऐसे क्षेत्र में समाविष्ट किसी भूमि का उपयोग, ऐसी

अंतिम विकास योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि के लिये भूमि उपयोग के संपरिवर्तन के लिये उपबंध।

विकास योजना में, आबंटन, आरक्षण या निर्देशन के रूप में दिखाये गये उपयोग के लिये, संपरिवर्तन किया गया समझा जायेगा तथा धारा ४२ तथा धारा ४४ के अधीन कोई अलग अनुमति, ऐसी विकास योजना के अधीन अनुज्ञेय उपयोग के लिये, ऐसी भूमि के उपयोग के लिये, आवश्यक नहीं होगी:

सन् २०१७ का महा. ३०। परंतु, जहाँ अंतिम विकास योजना, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसे इसमें आगे, "प्रारंभण दिनांक" कहा गया है) के प्रारंभण के दिनांक को या के पूर्व पहले से ही प्रकाशित की गयी हैं, वहाँ ऐसे विकास योजना के अधीन समाविष्ट क्षेत्र में कोई भूमि, यदि उप-धारा (२) में यथा-उपबंधित संपरिवर्तन कर, अकृषक निर्धारण तथा जहाँ लागू हो, नजराना या प्रीमिअम तथा अन्य सरकारी देय का भुगतान किया गया हैं, तो, ऐसी अंतिम विकास योजना में ऐसी भूमि के संबंध में, आबंटन, आरक्षण या निर्देशन के रूप में दर्शाये गये उपयोग के लिये संपरिवर्तन की गई समझी जायेगी।

(२) किन्ही क्षेत्र में अंतिम विकास योजना के प्रकाशन पर, जहाँ अंतिम विकास योजना पहले से ही प्रकाशित हुई है, प्रारंभण दिनांक के पश्चात्, कलक्टर, इस संबंध में किये गये आवेदन पर स्वप्रेरणा से, धारा ४७क में उल्लिखित दर पर संपरिवर्तन कर तथा विकास योजना में दर्शाये गये उपयोग के आधार पर, ऐसी भूमि के अकृषक निर्धारण अभिनिर्धारित करेगा या अभिनिर्धारण का प्रबंध करेगा तथा उसकी सूचना, उसका भुगतान करने के लिये संबंधित अधिभोगी को देगा:

परंतु, जहाँ ऐसी भूमि अधिभोगी वर्ग-दो के रूप में धारण की गइ है, वहाँ, कलक्टर, दस्तावेजों, जिनके, द्वारा, ऐसी भूमि मंजूर की गई है और संबंधित विधियाँ, नियमों तथा सरकारी आदेशों, जिसके द्वारा ऐसी भूमि प्रशासित की गई है, की भी जाँच करेगा और यदि अंतिम विकास योजना में दर्शाये गये उपयोग के लिये, संपरिवर्तन, तद्धीन अनुज्ञेय है, तब, कलक्टर जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, ऐसी संपरिवर्तन, की अनुमित देने के लिये, सक्षम प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की प्राप्ति के पश्चात्, सरकार के विशेष तथा सामान्य आदेशों के अनुसार, ऐसे संपरिवर्तन के लिये देय नजराना या प्रीमिअम या अन्य सरकारी देयों, उपरोक्त संपरिवर्तन कर तथा अकृषक निर्धारण की रकम के साथ, अभिनिर्धारित करेगा, तथा भुगतान करने के लिये अधिभोगी को वही संसूचित करेगा तथा यदि, अधिभोगी द्वारा उसी का भूगतान किया गया है, तब, कलक्टर, उसके भुगतान से साठ दिनों की अविध के भीतर नियमों के अधीन विहित प्ररूप में उसे सनद उसे प्रदत्त करेगा। सनद के जारी करने पर, यथा उपरोक्त भुगतान के दिनांक से प्रभावी, ऐसी भूमि अकृषक उपयोग के लिए संपरिवर्तन की गई है, दर्शाये गये अधिकारों के अभिलेख में, आवश्यक प्रविष्टी की जायेगी:

परंतु आगे यह कि, जहाँ, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही, इस संबंध में किये गये आवेदन पर की गई है, वहाँ, सूचना संपरिवर्तन कर तथा अकृषक निर्धारण के अभिनिर्धारण के पश्चात्, तथा जहाँ लागू हो, सरकार के अभिभावी आदेशों के अनुसार **नजराना** या प्रीमिअम या अन्य सरकारी देयों के जिरए सरकार को देय रकम,—

- (क) आवेदन के दिनांक से ३० दिनों के भीतर, अधिभोगी वर्ग-**एक** के रूप में धारण की गई भूमि के संबंध में ;
  - (ख) अधिभोगी वर्ग-दो के रूप में धारण की गई भूमि के संबंध में,—
  - (एक) आवेदन के दिनांक से ३० दिनों के भीतर, जहाँ, कलक्टर, उसके स्तर पर, ऐसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने के लिये अनुमित देने के लिये सक्षम हैं;
  - (दो) दिनांक, जिस पर, ऐसे अंतरण या उपयोग के परिवर्तन की अनुमित देने के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमित, कलक्टर द्वारा प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर ;

संबंधित अधिभोगि को जारी की जायेगी:

परंतु यह भी कि, इस धारा के अधीन किये गये अकृषक निर्धारण, जहाँ आवश्यक हो, योजना प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त विकास अनुमित के अनुसरण में, भूमि के लिये पुनरीक्षित किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिये, ऐसी अनुमित या यिद कोई हो, उसके पुनरीक्षण की मंजूरी के दिनांक से ३० दिनों के भीतर,

प्रत्येक मामले में, कलेक्टर को, ऐसी विकास अनुमित की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना, योजना प्राधिकरण को अनिवार्य होगा :

परंत् यह भी कि, विकास योजना में दर्शाये गये उपयोग के आधार पर किया गया भूमि का अकृषक निर्धारण, सरकार द्वारा, विकास योजना के पुनरीक्षित या परिवर्तित करने के मामले में, पुनरीक्षित किया जायेगा और उसके परिणामस्वरूप, ऐसे पुनरीक्षण या उपांतरण के दिनांक से, विकास योजना परिवर्तनों में दर्शाये गये भूमि के उपयोग का बदलाव, प्रभावी होगा :

परंतु यह भी कि, इस उप-धारा के अधीन संपरिवर्तन कर, इस उप-धारा के अधीन अकृषक निर्धारण तथा **नजराना** या प्रीमिअम या देय अन्य सरकारी देयों के भुगतान का **चलान** या प्राप्ति, अंतिम विकास योजना में दर्शाये गये अकृषक उपयोग के लिये संपरिवर्तित की गई है, के सबूत के रूप में मानी जायेगी और इससे अतिरिक्त सबूत आवश्यक नहीं होगा।

- (३) उप-धाराएँ (१) तथा (२) की कोई बात, विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये, धारा ३१ या ३८ के अधीन सरकार द्वारा अनुदत्त किसी भूमि या सुसंगत विधि के अधीन सरकार द्वारा अर्जित तथा किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को उपयोग के लिये सौंपी गई किसी भूमि या कोई भूमि जो विकास योजना में किसी आरक्षण के अधीन है किंत्, योजना प्राधिकरण या सम्चित प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं की गयी है, को लागू नहीं होंगी।
- प्रारूप प्रादेशिक (१) जहाँ, भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जिसके लिये प्रारूप प्रादेशिक योजना तैयार की गई है और योजना में ऐसे प्ररूप प्रादेशिक योजना से संबंधित आवश्यक सूचना सम्य्कतया राजपत्र में प्रकाशित की गई है या ऐसी समाविष्ट भूमि के प्रादेशिक योजना अनुमोदित की गई है और **राजपत्र** में प्रकाशित की गई है वहाँ, धारा ४२ या धारा ४४ के प्रयोजनों उपयोग के संपरिवर्तन के के लिये ऐसी भूमि का उपयोग, तत्समान अकृषक उपयोग के लिये संपरिवर्तित किया गया समझा जायेगा, यदि इस लिये उपबंध। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या अधिभोगी वर्ग-दो के रूप में धारण की गई भूमि के संबंध में, ऐसे संपरिवर्तन के लिये उद्ग्रहीत संपरिवर्तन कर या अकृषक निर्धारण, **नजराना** या प्रीमिअम या अन्य सरकारी देय सरकार के अभिभावी आदेशों तथा विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किये जाने पर एकबार, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर सन् १९६६ योजना अधिनियम, १९६६ की धारा १८ के अधीन ऐसी भूमि पर विकास की अनुमित मंजूर होगी।

का महा. ३७।

(२) जहाँ भूमि, क्षेत्र में स्थित है, जिसके लिये, प्रारूप प्रादेशिक योजना या प्रारूप विकास योजना तैयार की गई है तथा ऐसे प्रारूप प्रादेशिक योजना या प्रारूप विकास योजना के संबंध में आवश्यक सूचना **राजपत्र** में सम्यक्तया प्रकाशित की गई है, या ऐसी प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, विकास योजना अनुमोदित की गई है तथा राजपत्र में प्रकाशित की गई है, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा १८ के अधीन सन् १९६६ कलक्टर द्वारा या उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन योजना प्राधिकारी द्वारा कृषि भवन बनाने की दी गई का महा. अनुमित, ऐसे कृषि भवन के लिये धारा ४१, के विचाराधीन दी गई अनुमित समझी जायेगी।"।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४८ में संशोधन।

- उक्त संहिता की धारा ४८ की, उप-धारा (७) में, ''पाँच गुना के समान'' शब्दों के स्थान में, ''पाँच गुना तक" शब्द रखे जायेंगे।
- कठिनाई के निराकरण की

(१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंधों को प्रभावी सन् १९६६ करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित उक्त संहिता के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अविध के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ५. (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र.

अध्या. क्र. (२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के २ का निरसन २। अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा तथा व्यावृत्ती। संशोधित, उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2017.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (LEVY, AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १३ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,

प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

### MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, **"महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र राज्य में प्रवर्तित कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में प्रवर्तित कितपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अइसठवे वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

#### प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम तथा **१.** (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, <sup>प्रारंभण।</sup> २०१७ कहलाए।
  - (२) इस अधिनियम में जैसा कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-
    - (क) धाराएँ ३, ४, ५ और ६, १ अप्रैल २०१७ से प्रवृत्त होगी ; और
    - (ख) शेष धाराएँ, **राजपत्र** में इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

अध्याय दो

## महाराष्ट्र गन्ने पर क्रय कर अधिनियम, १९६२ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ९ की धारा १२ ख में संशोधन। २. महाराष्ट्र गन्ने पर क्रय कर अधिनियम, १९६२ की धारा १२ ख, की—

- सन् १९६२ · का महा.
- (१) उप-धारा (१) के, खण्ड (इ) में, "और २०१४-१५" शब्द और अंकों के स्थान में, का महा. "२०१४-१५, २०१५-१६ तथा २०१६-१७" अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;
  - (२) उप-धारा (२), अपमार्जित की जायेगी।

### अध्याय तीन

## महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५

३. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे, सन् १९७५ का हा. ९। इस अध्याय में, "वृत्ति कर अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, तृतीय परंतुक में, "आठ वर्षों से अधिक" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "जो भी पहले हो" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जाएगा, अर्थात् :--

''जिस वर्ष में नामांकन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या जिस वर्ष में उसके विरुद्ध में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है, उस वर्ष के, जो भी पहले हो, के सद्य पूर्ववर्ती वर्ष के अंत से,—

- (क) १ अप्रैल, २०१७ को या के पश्चात्, नामांकन प्रमाणपत्र प्रदान करने के मामले में, चार वर्ष से अधिक नहीं होगी,
  - (ख) किन्हीं अन्य मामले में, आठ वर्षों से अधिक नहीं होगी।"।
- वृत्ति कर अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्न धाराएँ, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

सन् १९७५ का महा. १६ की धाराएँ ४क और ४ख की निविष्टि।

**"४ क**. नियोक्ता, जिसे १ अप्रैल २०१७ को या के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया कर के भुगतान है, जिस वर्ष में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या जिस वर्ष में उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की कार्यवाही शुरु की गई है, जो भी पहले हो, के सद्य पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों से अधिक अवधि के लिये, कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

४ ख. (१) राज्य सरकार, समय-समय से, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के वर्गों कितपय मामलों में के लिये, जो, उक्त अधिसूचना में उल्लेखित किये गये, एजंट को भुगतान किये गये या भुगतान योग्य किमशन की रकम में से ऐसे कमिशन के भुगतान से पूर्व कर में, कटौती करेगा, उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार कर की कटौती के लिये अधिसूचित व्यक्ति, उक्त अधिसूचना में उपबंधित रित्या और अधिनियम की अनुसूची एक की प्रविष्टि १क में विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान करेगी।

तथा भगतान का

- (२) अधिनियम के अधीन, नियोक्ता तथा कर्मचारी से संबंधित सभी उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन समेत उप-धारा (१) के अधीन, कर की कटौती करने के लिये दायी व्यक्ति और व्यक्तियों को जिनसे ऐसे कर की कटौती करनी है, ऐसे लागू होंगे।"।
- वृत्ति कर अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (२) में, "सरल व्याज का भुगतान" शब्दों से प्रारम्भ सन् १९७५ का होने वाले और "भुगतान किये बिना शेष रहे" शब्दों से समाप्त होने वाले प्रभाग के स्थान में, "ऐसे कर की रकम के <sup>महा</sup>. <sup>१६</sup> की धारा अतिरिक्त में, अंतिम दिनांक, जब तक उसमें कर भरना जरुरी है, के पश्चात्, प्रत्येक महिने या उसके भाग के लिये, ऐसे कर की रकम पर, विहित दर पर परिगणित की गयी रकम, का सरल व्याज द्वारा भुगतान किया जायेगा" शब्द रखे जायेंगे।

९ में संशोधन।

वृत्ति कर अधिनियम की संलग्न अनुसूची एक में,—

(१) प्रविष्टि १ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— "१ क. धारा **४ ख** के अधीन प्रति वर्ष २५०० रु. "; यथा अधिसचित व्यक्तियाँ।

सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची एक में संशोधन ।

(२) प्रविष्टि २० के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— "२० क. वित्त अधिनियम,१९९४ के प्रति वर्ष २५०० रु. "; अधीन रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रबंधक।

#### अध्याय चार

## महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियम, २००३ में संशोधन।

- सन् २००३ का महा. ४ के अधीन बनाए गए नियम ८ में संशोधन।
- ७. महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालो के प्रवेश पर कर नियम, २००३ के नियम ८ के,—
- (१) उप-नियम (१) अपमार्जित किया जायेगा और १ अप्रैल २००५ से अपमार्जित किया गया समझा जायेगा ;
- (२) उप-नियम (३) के स्थान में, निम्न उप-नियम रखा जायेगा और १ अप्रैल २०१५ से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—
  - "(३) अरजिस्ट्रीकृत आयातकर्ता का निर्धारण, निर्धारण प्राधिकरण द्वारा, जिसकी अधिकरिता में विनिर्दिष्ट माल का उपभोग, उपयोग या विक्री की गयी पायी या देखी गयी है, द्वारा किया जायेगा।"।

#### अध्याय पाँच

## महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८ में संशोधन।

- **८.** महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "मूल्यवर्धित कर सन् २००५ अधिनियम" कहा गया है) की धारा ८ की, उप-धारा (३घ) में, "आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से प्रभावी" शब्दों के का महा. स्थान में, "चाहे भूतलक्षीप्रभाव से या भविष्यलक्षी प्रभाव से " शब्द रखे जायेगें।
- सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।
- मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २३ की,—
  - (१) उप-धारा (७) में, –
  - (क) ''ऐसा निर्धारण'' शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और '' आयुक्त को '' शब्दों सें समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

"ऐसा निर्धारण", यदि उक्त आदेश, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, पहली अपील में बनाया गया है, तब अठारह महिनों की अविध के भीतर और किन्ही अन्य मामलों में, निर्धारण प्राधिकरण या, यथास्थिति, आयुक्त को उक्त आदेश में अंतर्विष्ट ऐसे तथ्यों या निदेशों की संसूचना के दिनांक से छत्तीस महिनों की अविध के भीतर किया जायेगा ";

- (ख) परंतुक में, "संबंधित ब्यौहारी " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " छत्तीस महिनों की अवधि " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :-
  - " निर्धारण प्राधिकरण या, यथास्थिति, आयुक्त से संबंधित व्यौहारी, संसूचना के उक्त दिनांक से पहले या अठारह महीने या, यथास्थिति, छत्तीस महीनों की उक्त अविध के बाद में ";
- (२) उप-धारा (११) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि, इस उप-धारा के अधीन किसी भी आवेदन पर, महाराष्ट्र कर विधि सन् २०१७ (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण पर या के पश्चात्, निर्धारण का महा. आदेश पारित होने के मामले में, विचार नहीं किया जायेगा।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २६ में संशोधन।

- १०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २६ की,—
  - (१) उप-धारा (५) के खण्ड (क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—
    "परंतु आगे यह कि, निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में, जिसमें व्यौहारी,
    जब निर्धारण आदेश पारित किया गया था, की सुनवाई के समय निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित
    या हाजिर नहीं हुआ था, तब प्रथम अपील मे, अपीलीय प्राधिकरण, उक्त निर्धारण आदेश,-
    - (एक) यिद, उक्त अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक के पूर्व, अपील दायर की है तो, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण से सन् २०१७ नौ महीनों के भीतर अपास्त कर सकेगा,

सन् २०१७ का महा. ३१। (दो) यदि, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण पर या के पश्चात् अपील दायर की गई है, तो दिनांक, जिस पर उक्त अपील दायर की गई है, से छह महिनों के भीतर अपास्त कर सकेगा,

और, धारा २३ की उप-धारा (७) के अधीन, नये निर्धारण के लिये, निर्धारण प्राधिकरण को वापिस भेजेगा। ";

- (२) उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-
- "(६क) महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक पर या के पश्चात्, पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, प्रथम अपील में, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, दायर नहीं की जायेगी, जब तक, जैसे कि लागू हो, ऐसी निम्न रकमों के कुल भुगतान के सबूत के साथ न हो,—
  - (क) आदेश के विरुद्ध किसी अपील के मामले में, जिसमें ऐसी घोषणा या, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के प्रस्तुत न करने के कारण, घोषणा या प्रमाणपत्र के विरुद्ध दावा अस्वीकार किया गया है तो उप-धारा (६) के परंतुक में यथा उपबंधित, कर की रकम,
  - (ख) आदेश के विरुद्ध किसी अपील के मामले में, जिसमें, उपर्युक्त खण्ड (क) में यथा विवरणित दावों की अस्वीकृति और अन्य आधार पर कर दायित्व भी अंतर्विष्ट है तब, ऐसा कर, जब तक खण्ड (क) में उल्लिखित से अन्य के आधार पर, कर दायित्व कर से संबंधित है तब तक, अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त कर की रकम के दस प्रतिशत के समान रकम,
  - (ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में वर्णित आदेश से अन्य, आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलकर्ता द्वारा, विवादग्रस्त कर की रकम के १० प्रतिशत के समान रकम,
  - (घ) केवल शास्ति अधिरोपित करनेवाले पृथक आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा, यथा निर्देशित, रकम का निक्षेप, जो किसी भी मामले में, अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त शास्ति की रकम से, १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :
  - परंतु, खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन निक्षेपित करने के लिये आवश्यक रकम, पचास करोड रुपयों से अधिक नहीं होगी ;
  - (६ख) कोई भी अपील, अधीकरण के समक्ष, आदेश जो महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण को या के पश्चात् पारित किया गया है, के विरुद्ध, दायर नहीं की जायेगी, जब तक यथा प्रयुक्त, निम्न रकम के कूल भुगतान के सबूत साथ न हो :—
    - (क) आदेश के विरुद्ध, जिसमें ऐसी घोषणा या, यथास्थिति, प्रमाणपत्र के प्रस्तुत न करने के कारण, घोषणा या प्रमाणपत्र के विरुद्ध, दावा अस्वीकृत करने के मामले में, उप-धारा (६) के परंतुक में यथा उपबंधित, कर की रकम,
    - (ख) आदेश के विरुद्ध, जिसमें उपरोक्त खण्ड (क) में यथाविवरणित, दावों की अस्वीकृति और अन्य आधार पर कर दायित्व भी अंतर्विष्ट है, तब ऐसा कर, जब तक खण्ड (क) में उल्लिखित से अन्य के आधार पर, कर दायित्व कर से संबंधित, तब तक अपीलकर्ता द्वारा विवादग्रस्त कर की शेष रकम के १० प्रतिशत के समान रकम,
    - (ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में वर्णित आदेश से अन्य, आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलकर्ता द्वारा, विवादग्रस्त कर की शेष रकम के १० प्रतिशत के समान रकम ;
    - (घ) किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, अधिकरण द्वारा यथा निर्देशित रकम:

सन् २०१७ का महा. ३१।

परंत्, खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन निक्षेपित करने के लिये आवश्यक रकम, पंद्रह करोड़ रुपयों से अधिक न हो ;

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (६ख) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये, "विवादग्रस्त कर की शेष रकम " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, विवादग्रस्त कर की रकम, उप-धारा (६क) की क्रमशः खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन, प्रथम अपील में, अपीलीय प्रधिकरण द्वारा, यथानिर्देशित भुगतान की गई रकम को विचार में लेने के पश्चात् बकाया शेष रकम, से है ;

(६ग) अपीलीय प्राधिकरण या, यथास्थिति, अधिकरण, उप-धारा (६क) या, यथास्थिति, उप-धारा (६ख) के अधीन, अपील दायर करने पर, विनिर्दिष्ट रित्या शेष विवादग्रस्त देयों की वसूली पर रोक लगाएगा। "।

सन् २००५ का २७ में संशोधन।

११. मुल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २७ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (क) में "एक सौ बीस दिन" महा. ९ की धारा शब्दों के स्थान में, ''एक सौ अस्सी दिन'' शब्द रखे जायेंगे।

सन् २००५ का ३० में संशोधन।

- १२. मुल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोड़ी महा. ९ की धारा जाऐगी, अर्थात् :--
  - "(५) राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, समय-समय से, उसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन,—
  - (एक) जो विक्रय कर विभाग के स्वचलन प्रणाली की तकनीकी समस्याओं के कारण, विहित अवधि के दौरान, कर अदा करने के लिये असमर्थ था, या
  - (दो) जिसे रजिस्ट्रीकरण देरी से प्राप्त हुआ है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारियों के किसी विहित वर्ग द्वारा देय किसी अवधि के संबंध में ब्याज के संपूर्ण या किसी भाग से छूट दे सकेगा।"।

सन् २००५ का ३७ में संशोधन।

- मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३७, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुन:क्रमांकित की जायेगी ; महा. ९ की धारा और, इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-
  - " (२) उप-धारा (१) में यथा उल्लिखित प्रथम प्रभार किसी कर, शास्ति, ब्याज, समपहृत राशि, जुर्माना या किसी अन्य रकम की अदायगी के लिये धारा ३२ की उप-धारा (४) में विनिर्दिष्ट अविध के अवसान पर सृजित की गई समझी जायेगी।"।

सन् २००५ का ४० में संशोधन।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४० में, " उप-धारा (६) " शब्द, कोष्टक और अंक के पश्चात् महा. ९ की धारा "या, यथास्थिति, उप-धारा (६ग)" शब्द, कोष्टक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४४ में संशोधन।

- १५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४४ की उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी सन् २०१३ जायेगी, अर्थात् :-
  - "(६) कंपनी अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अध्यधीन, किसी निजी कंपनी से चाहे वह विद्यमान या परिसमापन के अधीन हो या न हो, इस अधिनियम के अधीन वसूलीय किसी कर या अन्य रकम, किसी भी अवधि के लिये, चाहे किसी भी कारण के लिये, वसूल नहीं की जा सकेगी तब जो व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान, निजी कंपनी का निदेशक थी ऐसी प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह, वसुल न होने संबंधी उक्त कंपनी के कामकाज के संबंध में उसकी ओर से कोई उपेक्षा, अपकरण, या कर्तव्य का उल्लंघन का संबंध उससे माना नहीं जा सकेगा, यह साबित किये बिना, ऐसा कर या अन्य रकम अदायगी के लिये संयुक्ततः और पृथक्ततः अलग-अलग रुप से देनदार है।"।

सन् २००५ का ५३ में संशोधन।

- मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५३ की, उप-धारा (१) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्न १६. महा. ९ की <sup>धारा</sup> उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—
  - " (१क) महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ के सन् २०१७ प्रारम्भण को या के पश्चात्, जो प्रतिदाय देय है, के मामले में, यदि प्रतिदाय साठ दिनों से अधिक लम्बित है का महा. तो उप-धारा (१) के उपबंध, लागू होंगे।"।

मूल्यवर्धित कर अधिनियम की संलग्न **अनुसूची 'क**'में, प्रविष्टि ६३ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, सन् २००५ का जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

महा. ९ की संलग्न अनुसूची

- " ६४. जब उपभोग के लिये दिये गये से छोडकर, प्रक्रिया किये गये, अर्ध प्रक्रिया किये गये, अर्ध पका हुआ, तैयार-मिश्रण, खाने के लिये तैयार, छिलका उतारी गयी मीठी मकई के,—
- (१) उपभोक्ता से कर संग्रहित शुन्य प्रतिशत " 'क' में संशोधन। नहीं किया जायेगा।
- (२) सरकारी खजाने में कर अदा नहीं किया जायेगा।
- (क) जमे हए (फ्रोजन) स्थिति में, या
- (ख) हवाबंद डिब्बे में, या
- (ग) व्यापारिक नाम के अधीन,

चाहे बिक्री की गई हो, या न हो, १ अप्रैल २००५ से ३१ मार्च २०१६ तक की अवधि के दौरान की गई बिक्री।

#### अध्याय छह

## महाराष्ट्र लाटरी पर कर अधिनियम, २०१६ में संशोधन।

महाराष्ट्र लाटरी पर कर अधिनियम, २००६ की धारा ३ की, उप-धारा (१) की, **सारणी** की, प्रविष्टि सन् २००६ का सन २००६ का महा. १ के, स्तंभ (३) में, "७०,०००" अंकों के स्थान में, "१,००,०००" अंक रखे जायेंगे।

महा. ४३ की धारा ३ में संशोधन ।

#### अध्याय सात

## महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१२ में संशोधन।

१९. महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१२ की धारा १ की, सन् २०१२ का सन् २०१२ का महा. <sub>ट।</sub> उप-धारा (२) के,— महा. ८ की धारा १ में संशोधन।

- (१) खण्ड (क) में, "धारा २१" शब्द और अंकों के स्थान में, "धारा २१ की उप-धारा (१)" शब्दों, अंको और अक्षरों को रखा जायेगा और सदैव रखा गया समझा जायेगा ;
- (२) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, और सदैव निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात :--
  - " (क-१) धारा २१ की उप-धारा (२), ८ अप्रैल २०११ से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।"।

#### अध्याय आठ

किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के विधिमान्यकरण सन् २००३ का <sup>महा.</sup> होते हुए भी, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे, सन २०१७ इस अध्याय में, " संशोधन " अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व किसी भी समय में, महाराष्ट्र <sup>का महा.</sup> स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसे इसमें सन् २००५ आगे, इस अध्याय में, " प्रवेश कर से संबंधित विधि " कहा गया है) के उपबंधों के अधीन किसी निर्धारण या ऐसे का महा निर्धारण के संबंध में की गई कोई कार्यवाही या कृत कोई बात, ऐसे निर्धारण, या ऐसे निर्धारण के संबंध में की गई कोई कार्यवाही या कृत कोई बात के दिनांक पर विद्यमान हो तो महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा २३ के अधीन उपबंधित समय सीमा के भीतर की गई है तो उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेंगी मानों कि, संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित प्रवेश कर से संबंधित विधि के अधीन सम्यकृतया की गई, ली गई या की गई थी और तद्नुसार, ऐसे निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये सभी कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें, सभी प्रयोजनों के लिये, विधि के अनुसार कृत या की गई समझी जायेगी और सदैव कृत या की गई समझी जायेंगी।

भाग सात-३

(२) संदेह के निराकरण के लिये, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति को उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी निर्धारण, संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित प्रवेश कर से संबंधित विधि के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, रोकते हुए नहीं समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2017.

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक १३ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्रकाश हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING (AMENDMENT) ACT, 2017.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, **"महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १५ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९६६ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में का <sup>महा</sup>. अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम <sup>३७।</sup> अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

- **२.** महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया हैं) की धारा २ के, खण्ड (५-क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—
  - "(५-क) "प्रशमित संरचना" का तात्पर्य, भूमि का कोई विकास जिसके संबंध में, धारा १८ की उप-धारा (२-ख) के उपबंधों के अधीन कलक्टर द्वारा या धारा ५२-क के अधीन योजना प्राधिकरण द्वारा, यथा उद्ग्रहीत प्रशमन प्रभार, आधारभूत संरचना प्रभार और अधिमूल्य का ऐसी संरचना के स्वामी या अधिभोगी द्वारा भुगतान किया गया है और जो ऐसे भुगतान पर, कलक्टर, या, यथास्थिति, योजना प्राधिकरण द्वारा प्रशमित संरचना के रूप में घोषित किया गया हैं, में हैं ;"।
- **३.** मूल अधिनियम की धारा १८ की, उप-धारा (२-ख) में, "प्रशमन प्रभार" शब्दों के पश्चात्, "आधारभूत सन् १९६६ का संरचना प्रभार और अधिमूल्य" शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

  पहा. ३७ की धारा १८ में संशोधन।
  - ४. मूल अधिनियम की धारा ५२ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ५२-क की निविष्टि। प्रशमित संरचना के रूप में, कतिपय विकासों के संबंध में उपबंध। "५२-क. (१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या जहाँ, विकास योजना के क्षेत्र में, ३१ दिसंबर, २०१५ को या के पूर्व अप्राधिकृत विकास कार्यान्वित किया गया हैं; किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, आदेश या निदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, योजना प्राधिकरण के अनुरोध पर, जिसका अनुसरण करें ऐसी शर्तों तथा निबन्धन और प्रशमन प्रभार, आधारभूत संरचना प्रभार और अधिमूल्य का भुगतान, जिसे योजना प्राधिकरण, ऐसे विकास को प्रशमित संरचना के रूप में घोषित करें, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, प्रशमित संरचना के रूप में ऐसे विकास की घोषणा पर, ऐसी संरचना के स्वामी या अधिभोगी के विरूद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, कोई अधिकतर कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी या निरंतर नहीं रखी जायेगी:

परंतु, किसी प्रशमित संरचना में, मरम्मत तथा रखरखाव के अलावा, कोई अधिकतर विकास, अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसी संरचना का कोई विकास का पुनर्संरचना केवल प्रचलित विकास नियंत्रण विनियमनों के उपबंधों के अनुसार होगा।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा ५३ में संशोधन। **५.** मूल अधिनियम की धारा ५३ की उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेंगी, अर्थात :—

"(१) (क) जहाँ, भूमि का कोई विकास, धारा ५२ की उप-धारा (१) के, खण्ड (क) या (ग) में संकेत किये गये अनुसार, कार्यान्वित किया गया है, वहाँ योजना प्राधिकरण, इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, स्वामी, विकासकर्ता या अधिभोगी को, ऐसा विकास होने से पहले की विद्यमान परिस्थिती में वैसा ही रखने, के लिये, उसे आवश्यक रहनेवाली २४ घंटे पूर्व की सूचना तामिल करेगा;

(ख) यदि, स्वामी, विकासकर्ता या अधिभोगी, तद्नुसार भूमि रखने में विफल होता हैं तो, योजना प्राधिकारी, ऐसे विकास को गिराने के लिये शीघ्र कदम उठाएगा और उसके लिये उपयोग किये गये या किये जानेवाले यंत्र उपकरणों और सामग्री पर रोक लगाएगा।

(१-क) जहाँ, धारा ५२ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ख) या (घ) में संकेत किये गये अनुसार, भूमि का कोई विकास, कार्यान्वित किया गया है, वहाँ, योजना प्राधिकरण, इस धारा के उपबंध के अधीन, स्वामी, विकासकर्ता या अधिभोगी को, उसे सूचना में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठाने के लिये अपेक्षित रखनेवाली एक महीने की सूचना, तामिल करेगा।"।

सन् १९६६ का महा. ३७ की धारा १४२ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १४२ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, जहाँ, १००० चौरस मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखंड पर अप्राधिकृत विकास कार्यान्वित किया गया है वहाँ कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होंगी।"।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक २४ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्र. हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६१ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर का <sup>महा.</sup> संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया <sup>२४।</sup> जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

सन १९६१ **२.** महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ८८ की, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के सन् १९६१ का का <sup>महा.</sup> पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़े जायेंगे अर्थात् :— प्राप्तिक परंतुक, जोड़े जायेंगे अर्थात् :— ८८ में संशोधन।

परंतु यह भी कि, सरकार, रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर या **स्व-प्रेरणा से,** कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियाँ को पूरा करने के लिए, समय-समय पर, यथावश्यक उक्त अविध को विस्तारित करेगी:

सन् २०१७ परंतु यह भी कि, इस उप-धारा के अधीन की कार्यवाहियों के मामले में, जो महाराष्ट्र सहकारी संस्था का <sup>महा.।</sup> (संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण की दिनांक को उपर्युक्त अविध के भीतर, पूरे नहीं किये गये हैं, सरकार, रिजस्ट्रार की रिपोर्ट पर या स्व-प्रेरणा से, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर के, उसे पूरा करनें के लिये, समय-समय पर, यथावश्यक उक्त अविध को विस्तारित कर सकेगी।"।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2017.

# THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक २५ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,

प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन सन् १९६६ करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया <sup>का महा.</sup> जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

सन् १९६६ का **२.** महा. ४१ में धारा अर्थात् :— २२ क की निविष्टि ।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा २२ के पश्चात्, निम्न दारा, निविष्ट की जायेगी, सन् १९६६ का महा. अर्थात् :— ४१।

गायरान भूमि के उपयोग के विचलन पर रोक।

- "२२क. (१) उप-धारा (२) या, यथास्थिति, (३) में उपबंधित परिस्थितियों को छोड़कर ग्रामीण पशुओं के खुले चरागाह के लिये कलक्टर द्वारा पृथक रखी गयी भूमि (जिसे इसमें आगे, "गायरान भूमी" कहा गया है) किसी अन्य उपयोग के लिये विचलन, मंजूर या पट्टे पर नहीं दी जायेगी।
- (२) ऐसी **गायरान** भूमि, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किन्ही कानूनी प्राधिकरण या किन्ही लोक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उपक्रम (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, ''लोक प्राधिकरण'' कहा गया है) द्वारा लोक प्रयोजन या लोक परियोजना के लिये विचलन, मंजूर या पट्टे पर दी जाय सकेगी, यदि ऐसे लोक प्रयोजनों या लोक परियोजनाओं के लिये सरकारी भूमि के अन्य यथोचित टुकडे उपलब्ध नहीं है।
- (३) **गायरान** भूमि, सरकारी प्राधिकरण न होते हुए, परियोजना प्रस्तावक के लिए किसी परियोजना के लिये परिवर्तन, मंजूरी या पट्टे पर दी जा सकेगी, जब ऐसी **गायरान** भूमि अपरिहार्य रुप से ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक हैं और उप-धारा (४) और (५) में यथा उपबंधित क्षतिपूरक भूमि ऐसा परियोजना प्रस्तावक राज्य सरकार को अन्तरित कर सकेगा।

(४) उप-धारा (३) के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जानेवाली क्षतिपूरक भूमि उस राजस्व ग्राम में **गायरान** भूमि के क्षेत्र से दुगने के समान होगी और उसका मूल्य उप-धारा (३) के अधीन इस प्रकार आंबटित **गायरान** भूमि के मूल्य से कम नहीं होगा:

परंतु, क्षतिपूरक भूमि का क्षेत्र जहाँ आवश्यक हो, यथोचित रुप से बढाया जायेगा, ताकि उप-धारा (३) के अधीन इस प्रकार आंबटित **गायरान** भूमि के मूल्य के लिये, उसके समान मूल्य हो।

- (५) उप-धारा (३) के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जानेवाली क्षतिपूरक भूमि, किसी अन्य विधि, तद्धीन बनाये गये नियम या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल खुले चरागाह या ग्रामीण पशुओं के उपयोग के लिये या घाँस या चारा आरक्षित के लिये धारा २२ के अधीन कलक्टर द्वारा समन्देशित की जायेगी।
- (६) इस धारा के अधीन भूमि के परिवर्तन या **गायरान** के पट्टे की मंजूरी, राज्य सरकार से अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जायेगी और धारा ३३० क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ, इससे अधीनस्थ किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी।

सन् २०१३ का ३०। स्पष्टीकरण.—(क) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "लोक प्रयोजन" अभिव्यक्ति का अर्थ, भूमि अर्जन, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ में इसे यथा समनुदेशित अर्थ के समान है।

(ख) उप-धारा (३) के अधीन परियोजना के लिये, जहाँ ऐसी भूमि अपरिहार्य रुप से आवश्यक है या नहीं है, यह प्रश्न विभागीय आयुक्त की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित किया जायेगा।"।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2017.

THE DR. VISHWANATH KARAD MIT WORLD PEACE UNIVERSITY ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक २९ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

> प्र. हिं. माली, प्रधान सचिव, विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट शासन।

### MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHEMENT,
INCORPORATION AND REGULATION OF DR. VISHWANATH KARAD
MIT WORLD PEACE UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT AND
ADVANCEMENT OF HIGER EDUCATION IN THE STATE AND TO
PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR
INCIDENTAL THERETO.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ मई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा, के विकास और उन्नित के लिए डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्व शांति विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए के लिये उपबंध तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नित के लिए डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी विश्व शांति विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

- संक्षिप्त नाम तथा **१.** (१) यह अधिनियम डॉ. विश्वनाथ कराड **एमआयटी** विश्व शांती विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ <sup>प्रारंभण।</sup> कहलाए।
  - (२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
  - परिभाषाएँ। २. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
    - (क) "प्रबंध मंडल बोर्ड" का तात्पर्य, धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;
    - (ख) "परिसर" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है;
    - (ग) "दूरस्थ शिक्षा" का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्चक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

- (घ) " कर्मचारी" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;
- (ड) "फीस" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है;
  - (च) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;
  - (छ) "शासी निकाय" का तात्पर्य, धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;
- (ज) "उच्चतर शिक्षा" का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;
- (झ) "छात्रावास" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;
  - (ञ) "अधिसूचना" का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;
  - (ट) " राजपत्र" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र से है ;
- (ठ) "विहित" का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;
- (ड) "विनियमित निकाय" का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादिमक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय औषध परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है;
  - (ढ) "नियम" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;
  - (ण) "धारा" का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;
- (त) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, संस्था रिजिस्ट्रिकरण अधिनियम, १८६० और महाराष्ट्र लोकन्यास अधिनियम के अधीन न्यास के रुप में महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजीनिअरिंग एण्ड एज्युकेशनल रिसर्च, पूणे से है ;
  - (थ) "राज्य" का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;
- (द) "परिनियम", "आर्डिनन्सो" तथा "विनियमों" का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;
- (ध) "छात्र" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादिमक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;
- (न) "अध्ययन केंद्र" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;
- (प) "अध्यापक" का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररुप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है;
- (फ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये डॉ. विश्वनाथ कराड **एमआयटी** विश्व शांति विश्वविद्यालय, पुणे से है।

सन् १८६० का २१। सन् १९५० का २९।

- विश्वविद्यालय का **३.** (१) डॉ. विश्वनाथ कराड **एमआयटी** विश्व शांति विश्वविद्यालय, पुणे के नाम से एक विश्वविद्यालय <sup>निगमन</sup>। स्थापित किया जाएगा।
  - (२) अध्यक्ष, कुलपित, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादिमक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, या सभी एतदद्वारा "डॉ. विश्वनाथ कराड **एमआयटी** विश्व शांती विश्वविद्यालय, पुणे" के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे।"।
  - (३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।
  - (४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रुप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा और उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।
  - (५) विश्वविद्यालय स्थित होगा और उसका मुख्यालय डॉ. विश्वनाथ कराड **एमआयटी** विश्व शांती विश्वविद्यालय, पुणे ४११ ०३८ महाराष्ट्र में होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

- ४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न नुसार होंगे,-
- (क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजिनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना;
- (ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;
- (ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना :
  - (घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;
- (ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुर्नीनर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना।
  - (च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना ;
  - (छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;
- (ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपायोजन के लिए ;
- (झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;
- (ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना :
- (ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोन के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;
- (ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

- (ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादिमक विशेषताएँ गठित करना ;
- (ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादिमक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोन को संस्थित करना ;
  - (ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;
- (त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादिमक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, १९८७ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठीत भारतीय बार परिषद, या यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।
- ५. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

- (एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धितयों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धित सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;
- (दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादिमक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;
  - (तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;
- (चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;
  - (पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;
- (छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;
  - (सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;
- (आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रावृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;
- (नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछडे स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;
  - (दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;
- (ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;
  - (बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;
  - (तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;
- (चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

सन् १९८७ का ५२।

सन् १९९३

सन् १९५६

का ३। सन् १९४८

का ८।

सन् १९६१ का २५।

- (पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारियों के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढावा देना तथा प्रवर्तन करना :
- (सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;
- (सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मित कराना ;
- (अठराह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, तट-मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;
- (उन्नीस) दान, बिक्षस, अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पित्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पित्ति सिम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;
- (बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;
- (इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना :
  - (बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;
- (तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रामिक, मानदेय अवधारण करना ;
  - (चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;
  - (पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;
- (छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापिस लेना ;
- (सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;
- (अड्डाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढावा देने के लिए व्यवस्था करना ;
- (उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजिनक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;
- (तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;
- (इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय निकायों या सिमितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य सब के लिए खुला रहेगा। अकादिमक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अवर्जित नहीं किया जाएगा।

- (२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरिधसूचित जनजातियों, (विमुक्त जातियों)। खानाबदोष जनजातियों, एसबीसी-के (विशेष पिछडा वर्ग) पिछडे वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा ।
- (३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।
- विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायता पाने विश्वविद्यालय का हकदार नहीं होगा।

स्ववित्तपोषित होगा।

- ८. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी विन्यास निधि। निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम पाँच करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे स्व-प्रेरणा से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।
- (२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों का के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।
- (३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तदधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहृत करने की शिक्त होगी।
- (४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।
- (५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभृत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।
- (६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भूनाने का अधिकार होगा ।
- ९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया साधारण निधि । जाएगा, अर्थात्:-
  - (एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;
  - (दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;
  - (तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;
  - (चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा ;
  - (पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ ।

सामान्य निधि का १०. सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती उपयोग। या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

> परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

## विश्वविद्यालय के

- ११. विश्वविद्यालय के, अधिकारी निम्न होंगे, अर्थात् :—
- अधिकारी ।
- (एक) अध्यक्ष ;(दो) कुलपित ;
- (तीन) संकायाध्यक्ष ;
- (चार) रजिस्ट्रार ;
- (पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;
- (छह) परीक्षा नियंत्रक ; और
- (सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।
- अध्यक्ष । **१२.** (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अविध के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
  - (२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और शर्तें, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।
    - (३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।
  - (४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादिमक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
    - (५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :--
    - (क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;
      - (ख) कुलपित की नियुक्ति करना ;
      - (ग) धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपित को हटाना;
      - (घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

## अध्यक्ष को हटाना।

- **१३.** अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—
  - (क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;
  - (ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;
  - (ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है :
  - (घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या
  - (ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शिक्तयों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकृल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुर्नपाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

**१४.** (१) कुलपित, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से पिरिनियमों द्वारा कुलपित। विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अविध के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपित, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपित, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपित के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अविध, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादिमक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पदित करेगा।
  - (३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (४) यदि, कुलपित की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शिक्तयाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है:

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपित द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

- (५) यिद, कुलपित की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए पिरिनियमों, ऑिडनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- (६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।
- (७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपित का पद पर बने रहना विश्वद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपित को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपित को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

- **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्यामें और सेवा के ऐसे निबन्धनों संकायाध्यक्ष। और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादिमक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपित का सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपित द्वारा सौंपी जाए ऐसी शिक्तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।
- **१६.** (१) रिजस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और रिजस्ट्रार। शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

- (२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासिनक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन उसे करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।
- (३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादिमक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।
- (५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपित द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

- **१७.** (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपित के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।
- (३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतिनक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपित के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अविध के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अविध के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसे होंगे।
  - (४) परीक्षा नियंत्रक,—
    - (क) अग्रिम में परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;
    - (ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;
    - (ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;
  - (घ) परीक्षाओं से संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;
  - (ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादिमक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।
- (५) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।
- मुख्य वित्त तथा **१८.** (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा <sup>लेखा अधिकारी।</sup> अधिकारी होगा।
  - (२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
  - (३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।
- अन्य अधिकारी। **१९.** (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।
  - (२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबन्धन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

- (एक) शासी निकाय ;
- (दो) प्रबंध मंडल बोर्ड ;
- (तीन) अकादिमक परिषद ;
- (चार) परीक्षा बोर्ड ; और
- (पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।
- २१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— शासी निकाय।
  - (एक) अध्यक्ष ;
  - (दोन) कुलपति ;
  - (तीन) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे ;
- (चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;
  - (पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;
  - (छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;
- (सात) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- (२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।
- (३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात :-
- (क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शिक्तयों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पृष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;
  - (ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;
  - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना : और
  - (च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।
- (५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।
- २२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

प्रबंधमंडल बोर्ड।

- (एक) कुलपति ;
- (दो) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य;
- (तीन) कुलपित से चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;
- (चार) तीन व्यक्ति, शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है; और
- (पाँच) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

- (२) कुलपति, प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा।
- (३) प्रबंध मंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (४) प्रबंध मंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।
- (५) प्रबंध मंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादिमक **२३.** (१) अकादिमक परिषद, कुलपित और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों परिषद। द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (२) कुलपति, अकादिमक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
- (३) अकादिमक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादिमक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादिमक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
- (४) अकादिमक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- २४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धित में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति परीक्षा बोर्ड। के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रो या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यिक्षक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सिम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति .. अध्यक्ष ;

(दो) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक . . सदस्य ;

(तीन) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ . . सदस्य ;

(चार) परीक्षा नियंत्रक . . सदस्य सचिव ।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए ।

विश्वविद्यालय के **२५.** विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों अन्य प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य।

निरहंता। **२६.** कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निर्र्ह होगा, यिद वह,—

- (क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है;
- (ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;
- (ग) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या
- (घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्विवद्यालय के २७. विश्विवद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति किसी प्राधिकरण के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होंगी। या निकाय की

किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

- **२८.** किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा अस्थायी रिक्तियों या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकास का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदाविध के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।
- **२९.** (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी सिमितियों सिमितीयाँ। द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें सिमितियाँ गठित करेंगे।
  - (२) ऐसी सिमितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- **३०.** (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासकीय निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके प्रथम परिनियम। अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- (२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—
  - (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;
    - (ख) कुलपित की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;
  - (ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;
  - (घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य;
    - (ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम के लिए प्रक्रिया ;
    - (च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;
  - (छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;
  - (ज) आरिक्षत सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और
    - (झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध ।
- (३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार मिहने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।
- (४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा ।
- **३१.** (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय पश्चात्वर्ती के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :
  - (क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

- (ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;
- (ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;
- (घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुन:संरचना करना ;
- (ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;
- (च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सुजन करना ;
- (छ) फीस का पुनरीक्षण;
- (ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और
- (झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले है ।
- (२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे ।
- (३) प्रबंध मंडल बोर्ड समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंध मंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

- **३२.** (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलमित द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे ।
- (२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थातु:—
  - (क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;
  - (ख) विश्वविद्यालय की उपिधयों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;
  - (ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादिमक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;
    - (घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;
  - (ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;
  - (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;
    - (छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में विद्यार्थियों के आवास की शर्ते;

- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध;
- (झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;
- (ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और
- (ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मृहैया करना अपेक्षित है ।
- (३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपित द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यिद कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।
- **३३.** (१) अकादिमक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स प्रबंध मंडल पश्चातवर्ती बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे । <sup>ऑर्डीनेन्स</sup>।
- (२) अकादिमक परिषद, या तो प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सिम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतिरत करेगी या सुझावों को सिम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यिद कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादिमक परिषद के सुझावो का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।
- **३४.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण प्रबंध मंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के विनियम। कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तदुधीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।
  - **३५.** (१) विश्वविद्यालय मे प्रवेश गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे। प्रवेश।
- (२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे ।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरिधसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी:

परंतु, किसी मामले में कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- (४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से सत्तर प्रतिशत सीटें आरक्षित रखीं जायेगी।
- **३६.** (१) विश्वविद्यालय, समय-समय से अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और इस प्रयोजन के फीस संरचना। लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को उसके अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी।
- (२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी ।
- (३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित सिमिति के लिए अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा। सिमिति का अध्यक्ष मुंबई की व्यक्ति जो, उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश से होगा।
- (४) सिमिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा चाहे प्रस्तावित फीस:— भाग सात—६

- (क) के लिए पर्याप्त-
  - (एक) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने के लिए उत्पादन स्रोत ; और
  - (दो) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और
- (ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं है।
- (५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो फीस संरचना का अनुमोदन करेगा । सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक शेष वैध रहेगी ।
- (६) राज्य सरकार विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी या कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी ।
- (७) विश्वविद्यालय उप धारा (५) के अधीन जिसके लिये हकदार है, उससे अन्य कोई फीस चाहे किसी भी नाम से हो, प्रभारित नहीं करेंगी।

प्रति व्यक्ती फीस का प्रतिषेध ।

- **३७.** (१) कोई प्रतिव्यक्ति फीस, विश्वविद्यालय द्वारा या की और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नित के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।
- (२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधन रोक़ड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास निधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चिलत किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी । जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के सन १९८८ का ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ महा. ६। की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।
- परीक्षाओं की **३८.** प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून समय सारणी। से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा:
  - परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।
- परिणामों की **३९.** (१) विश्वविद्यालय विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों घोषणा । की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यिद, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अविध के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा ।

- (२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।
- ४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत <sub>दीक्षांत समारोह ।</sub> समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक **(एनएएसी),** बैंगलोर से उसके <sub>प्रत्यायन ।</sub> संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चातु, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।
- ४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

- (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन मंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों वार्षिक रिपोर्ट । में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।
  - (२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।
  - (३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।
- ४४. (१) प्रबंध मंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा वार्षिक लेखा और तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में <sup>संपरीक्षा</sup> । कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।
  - (२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तृत की जाएगी।
- (५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- ४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ विश्वविद्यालय अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपित से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे <sup>निरीक्षण करने की</sup> व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

सरकार की शक्ति ।

- (२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।
- (३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।
- ४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम प्रायोजक निकाय एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

परंत्, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगी :

परंत्, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय राज्य सरकार की विशेष शक्ति ।

- ४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये <sup>परिस्थितियों में</sup> गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उदभुत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।
  - (२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।
  - (३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।
  - (४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को, सिविल प्रक्रिया सन १९०८ संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध <sup>का ५।</sup> में वाद का विचारण करते समय होगीं, अर्थात् :--
    - (क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;
    - (ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;
      - (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और
      - (घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।
  - (५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की, इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ सन १९७४ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।
  - (६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तदुधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादिमक मानकों के संतर्जक से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।
  - (७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध मंडल बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पुरा नहीं किए हैं और उपाधि, डिप्लोमा या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

- (८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा ।
- (९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।
- ४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित सचिव स्तरीय स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुपालन <sup>समिति</sup> <sup>और</sup> के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय सिमिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग <sup>परिचालन</sup>। के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

- (२) उप-धारा (१) के अधीन गठित सिमिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये राजपत्र में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।
- (४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।
- **४९.** (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के <sub>नियम बनाने की</sub> लिए नियम बना सकेगी । शक्ति ।
- (२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
  - (क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;
  - (ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके ।
- (३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अविध के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यिद, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेगी ।
- ५०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, कठिनाई के जैसा अवसर उद्भृत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई निराकरण की बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंत्, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षो की अविध के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2017.

THE MAHARASHTRA PARAMEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमित दिनांक २९ अप्रैल, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,

प्रधान सचिव. विधि तथा न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन।

#### MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2017.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA PARAMEDICAL COUNCIL ACT, 2011.

## महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमित प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३ मई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

## महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ में संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ में संशोधन सन् २०१६ करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अङ्सठवें वर्ष में, एतद् द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया का महा. जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

- (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाएँ।
- (२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसें राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।
- सन २०१६ का महा. में संशोधन।
- महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) सन् २०१६ ६ के दीर्घ <sup>शीर्षक</sup> के दीर्घ शीर्षक में, ''पराचिकित्सा व्यवसायियों'' शब्दों के स्थान में, ''पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक'' <sup>का महा</sup> ६। शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा.

मुल अधिनियम की उद्देशिका में, "पराचिकित्सा व्यवसायियों" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा ६ की उद्देशिका में व्यवसाय करनेवाले कार्मिक'' शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा २ में संशोधन।

- मल अधिनियम की धारा २ में.-8.
  - (क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—
  - (ग-क) ''पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" का तात्पर्य, उसके आनुषंगिक सेवाओं या अध्यापन या व्यवसाय या मोडेम वैज्ञानिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक प्रणाली या यूनानी प्रणाली या के दोनों चिकित्सा की होम्योपेथिक प्रणाली में उसके मूल अधिभोग के रूप में, जुड़े हुए व्यक्ति से है ;";
  - (ख) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थातु :—
  - (एक) "रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" का तात्पर्य, धारा २६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक से है ;"।

मूल अधिनियम, की धारा ४ की, उप-धारा (१) में,—

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा ४ में संशोधन।

(क) खण्ड (५) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(पाँच-क) महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष, **पदेन** सदस्य ;";

- (ख) खण्ड (सात) में, "पराचिकित्सा व्यवसायियों" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा १९ की, उप-धारा (२) में,—

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा

- (क) खण्ड (घ) में, ''पराचिकित्सा व्यवसायियों'' शब्दों के स्थान में, ''पराचिकित्सा व्यवसाय १९ में संशोधन। करनेवाले कार्मिक'' शब्द रखें जायेंगे।
- (ख) खण्ड (ङ) में, "पराचिकित्सा व्यवसायियों" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा २२ में,—

सन् २०१६ का

- महा. ६ की धारा (क) उप-धारा (३) में, "पराचिकित्सा व्यवसायियों" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय <sub>२२ में संशोधन।</sub> करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।
- (ख) उप-धारा (४) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों. के स्थान में, ''पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक'' शब्द रखें जायेंगे।
- (ग) उप-धारा (५) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा २१ में,—

सन् २०१६ का

महा. ६ की धारा (क) उप-धारा (१) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय २६ में संशोधन। करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।

- (ख) उप-धारा (२) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक'' शब्द रखें जायेंगे।
- (ग) उप-धारा (३) में, ''पराचिकित्सा व्यवसायियों'' शब्दों के स्थान में, ''पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे।
- मुल अधिनियम की धारा २८ की, उप-धारा (२) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के स्थान में, सन् २०१६ का महा. ६ की धारा "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे। २८ में संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्द दोनों स्थानों में, सन् २०१६ का महा. ६ की धारा जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाला कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे। ३१ में संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा ३२ में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्द दोनों स्थानों में जहाँ कहीं वे आये सन् २०१६ का महा. ६ की धारा हों, के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाला कार्मिक" शब्द रखें जायेंगे। ३२ में संशोधन।

(यथार्थ अनुवाद)

#### हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक.

महाराष्ट्र राज्य।